14.16 hrs.

INDIAN RAILWAYS (SECOND AMENDMENT) BILL Contd.

Clause 3—Contd.

श्री शिव नारायण (बस्ती) : सभापति महोदय, कल शाम को इस गवर्नमेन्ट की पोजीशन बड़ी आकवर्ड हो गई थी। मेरे लायक मित्र नम्बियार साहब बड़े हमदर्द थे। रेलवे विभाग के अमेण्डमेन्ट बिल पर जब उपाध्यक्ष महोदय ने उनको काल किया तो वह दब गये, अपनी ड्यूटी को उन्होंने इस हाउस में पूरा नहीं किया। इन शब्दों को कहते हुए मैं माफ़ी चाहूँगा—

As a Member of Parliament he had failed in his duty to raise it, and I am coming to his aid, not to the aid of Government, I take up the proceedings where they should have been taken up. I am very thankful to you for calling me today. His amendment is about ticketless travellers.

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : जब इन को पास नहीं मिला था तो ये विदाउट-टिकट चला करते थे।

श्री शिव नारायण : सभापति महोदय, चार महीनों के अन्दर आप देखें—बिना टिकट चलने वालों की संख्या रही है—

सैन्ट्रल रेलवे	6,68 291
ईस्टर्न रेलवे	6,67,957
नार्दर्न रेलवे	3 57,437

इसी तरह से अन्य रेलों की संख्या को जोड़कर कुल 39,93,423 लोग चार महीने के अन्दर बिना-टिकट पकड़े गये।

इस सरकार को यह अपोजीशन गाली देती है—ये निकम्मे हैं, इनको गोली मारना चाहिये, इन लोगों का फांसी देना चाहिये—जब कि इस सरकार ने केवल इतना ही किया है कि इन टिकटलैस ट्रेवलिंग को रोकने के लिये जुर्माना 10 रु० कर दिया है .....

एक माननीय सदस्य : 10 रु० जुर्माना कर रहे हो, गाली नहीं देंगे तो क्या करेंगे।

श्री शिव नारायण : मैं इस गवर्नमेन्ट से कहना चाहता हूँ कि आपने 10 रु० जुर्माना किया, वह ठीक है, लेकिन हमारे जो टिकट कलैक्टर्स हैं, चैकिंग करने वाले लोग हैं, इनको अपनी सुरक्षा के लिये कोई हथियार दो, पिस्तौल दो। उनकी लाइफ़ डेन्जर में है। मैं अभी हाल में लखनऊ से बस्ती फर्स्ट क्लास में ट्रेवल कर रहा था, एक स्टेशन पर दो आदमी फर्स्ट क्लास में चढ़ आये, उनके पास सैकण्ड क्लास का टिकट था। जब उनको चैक किया गया और कहा गया कि आप सैकण्ड क्लास में जाइये, तो वह बैठे रहे और फर्स्ट क्लास में बैठने के लिये ही इन्सिस्ट करते रहे। तब मैंने इन्टरवीन किया और उनको बैठा लिया। उस पर टी० टी० ने कहा कि अब आपकी रेस्पोन्सिबिलिटी है। वह उस आदमी को पिस्तौल से मार सकते थे। इसलिये मैं रेलवे मिनिस्टर से कहना चाहता हूं कि आप उनकी जानोमाल की हिफाजत के लिये कम से कम उनको पिस्तौल दो या कोई और हथियार दो। डण्डा भी रहे तो कोई हर्ज नहीं है।.....(**व्यवधान**)..... तुम्हारे लिये भी पिस्तौल रहेगी, घबराओ मत..... (**व्यवधान**).....

आज गवर्नमेन्ट पर ब्लैक मेलिंग के बड़े चार्जेज हैं, बड़ी शिकायत की जाती है, लेकिन जब गवर्नमेन्ट कोई कानून लाती है तो यह अपोजीशन बड़ी दुहाई देने लगता है। गवर्नमेंट ब्लैक मेलिंग को चैक करना चाहती है, इस बेईमानी और करप्शन को वाइप-आउट करने के लिये ही आनरेबिल मिनिस्टर साहब ने 8 आने पर 10 रु० जुर्माना कर दिया है...

एक माननीय सदस्य : आपको क्या मिला ? कुछ मिल गया होगा।

श्री शिव नारायण : आपसे क्या मिलेगा। भिखमंगे के पास क्या है। जिसके पास कुछ नहीं है, वह खाली हंडिया ही बजाता है, गाल बजायेगा, गालियां बकेगा, अन्नदाता ही दे सकता है, भिखारी नहीं दे सकता है। जिसके पास कुछ नहीं है, वह क्या देगा।

श्री जि० मो० बिस्वास (बांकुरा) : चैकिंग स्टाफ़ को रनिंग स्टाफ़ ट्रीट किया जाना चाहिये।

श्री शिव नारायण : यह रेलवे का नौकर रहा है.....

SHRI J. M. BISWAS : But he is not accepting my suggestion.

SHRI SHEO NARAIN : I am doing that now.

सभापति महोदय, मैं रेलवे बोर्ड के मेम्बरों से जो कि यहां बैठे हुए हैं यह कहना चाहता हूं कि वे जांच करें कोई भी पोलिटीशियन, पार्टी के लोग जो कि यूनियन्स में इन्ट्रेस्टेड हैं, वे शुड डू दि वर्क आनेस्टली। इससे मुल्क की नाक कटती है। मैं सन 67 में विदेश गया था और वहां पर मैंने ट्रेन्स की जो व्यवस्था देखी है वैसी व्यवस्था यहां पर नहीं है। अगर उसी प्रकार की व्यवस्था यहां पर भी की जाए तो 39 लाख टिकिटलैस ट्रेवेलर्स नहीं रहेंगे। फिर सभी क्लास के पैसेन्जर्स को आराम मिल सकता है।...(**व्यवधान**)... सरजू पांडे जी, मैं आप का दोस्त हूं, कल आप नहीं थे, मैंने आपको कोट किया था। आपने ही कल कहा था कि एक्सीडेंट जहां हुआ वहां तीन दिन पहले बढ़िया लाइन बनी हुई थी। जब ऐसी बात थी तो इसका यही मतलब है कि सैबोटाजिंग हुई वरना फिर वह लाइन कैसे उड़ गई ? मैं एक वकील की हैसियत से इसको साबित कर सकता हूं कि सैबोटाजिंग हुई।...(**व्यवधान**)... सभापति महोदय, जितना हमारा टाइम वेस्ट हुआ है वह हमें दीजियेगा।

MR. CHAIRMAN : This is the second reading. The hon. Member had already spoken. Now he should he very brief.

SHRI J. M. BISWAS : He is an all-party speaker and so he may be given some more time.

MR. CHAIRMAN : Let us now listen to the Member who is speaking.

SHRI SHEO NARAIN : You have authority here ; we shall obey you and not these people.

मैं अपने मित्र नंबियार साहब से कहना चाहता हूं : Those who will obey can give the orders ; those who will not obey cannot give the orders ; this is the verdict of the great commander Napoleon, I hope you will act on it. Do your duty properly in this House. This House is very supreme ; it is the supreme power of the country.

मैं आपका अनुग्रहीत हूं कि आपने मुझे बोलने का समय दिया। मैं रेलवे मिनिस्टर साहब से कहना चाहता हूं कि जो कमियां हैं उनकी वे पूर्ति करें। अगर आप काम नहीं कर सकते हैं तो आपको अलग हो जाना चाहिए। ...(**व्यवधान**)... हमारे डाक्टर साहब कोई कमजोर आदमी नहीं हैं। वे बढ़िया कांग्रेसी हैं जो कि गांधियन फिलास्फी में विश्वास करते हैं। ...(**व्यवधान**)... यादवजी, आप भी क्या बात करते हैं, दस महीने तक हमने आपकी सरकार भी देखी है। चरणसिंह की सरकार को हमने अच्छी तरह से देखा है। बाराबंकी और कानपुर में उस वक्त ज्यादा सैबोटाज होते थे। ...(**व्यवधान**)...

SHRI DHIRESWAR KALITA (Gauhati) : On a point of order.....

श्री शिव नारायण : ये भी ऐसे ही इलाके से आते हैं। आसाम में पाकिस्तानी इन्फिल्ट्रेटर आया करते हैं। As an Indian it is their duty to check them and contain the enemies.

तो मैं यह कह रहा था कि हमारे डाक्टर साहब कोई कमजोर आदमी नहीं हैं। वे राजपूत हैं और बढ़िया शासन करते हैं। मैं उनसे कहूंगा कि वे रेलवे बोर्ड को ठीक करें। और अगर वह ठीक तरह से फंक्शन न करें तो उस को सलाम कर लीजिए। इन शब्दों के साथ मैं रेलवे मिनिस्टर और नंबियार साहब को धन्यवाद देता हूं।

MR. CHAIRMAN : Shri S. C. Jha.

SHRI NAMBIAR : He has already spoken yesterday.

MR. CHAIRMAN : Did he speak on this clause yesterday.

SHRI SHIVA CHANDRA JHA (Madhubani) No, I spoke on cl. 2.

सभापति जी, क्लाज तीन में मेरा यह संशोधन है कि जहां पर दस रुपया रखा गया है उसकी जगह पर दो रुपये रखे जायें और जहां पर सरकार ने कहा है कि पांच रुपये का जुर्माना किया जाये, एक्सेस चार्जेज के लिए उसके लिए

[Shri Shiva Chandra Jha]

मेरा संशोधन है कि एक रुपया से ज्यादा न हो। कल जब मैं बोल रहा था तो मैंने कहा था कि यह बात सही है कुछ अंशों में यात्री जिम्मेदार हैं बिना टिकट यात्रा करने के लिए, दूसरे शब्दों में आप कह सकते हैं यदि एक परसेन्ट यात्री जिम्मेदार हैं, बिना टिकट चलने के लिए, तो सरकार 99 परसेन्ट जिम्मेदार हैं, उनको इस परिस्थिति में लाने के लिए कि वे बिना टिकट यात्रा करें। रेल मंत्रालय जनता पर जुर्माना करता है और सजा देता है लेकिन वह अपने ऊपर गौर नहीं कर रहा है कि जनता की सुविधा के लिए किन चीजों को हमें करने की आवश्यकता है। इस बारे में रेल मंत्रालय की ओर से पूरी ढिलाई है। दूसरी नयी सुविधाओं को तो छोड़ दीजिए, जितनी व्यवस्थायें इस समय मौजूद हैं यदि उन्हीं सुविधाओं को रेल मंत्रालय मुस्तैदी के साथ उपलब्ध कराये तो मैं समझता हूं जनता को बहुत कुछ फायदा पहुंच सकता है। लेकिन इस वक्त वह भी नहीं हो रहा है। पानी पिलाने की व्यवस्था का जहां तक सम्बन्ध है, हर स्टेशन और प्लेटफार्म पर वह व्यवस्था भी आप नहीं पायेंगे। इसी प्रकार से कितने ही उदाहरण दिये जा सकते हैं। बिहार में सकरी स्टेशन पर एक टिन-शैड, सौ फीट उत्तर और सौ फीट दक्षिण, बनाने की बात पहले से ही सैंक्शंड है लेकिन 50 फीट इधर और 50 फीट उधर ही बना है जिससे कि बारिश में यात्री भीगते हैं, बहुत बुरी तरह से, जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। फिर मंत्रालय की ओर से वह कार्य नहीं हो रहा है। इसी प्रकार से सकरी और पंडौल के बीच में हाल्ट बनाने की बात है। वह बात बहुत दूर तक आगे बढ़ चुकी है। मैं जब दिल्ली आ रहा था तो मुझे रास्ते में मालूम हुआ कि दिल्ली में यह बात अटकी हुई है, दफ्तर में बहुत सुस्ती के साथ कागज खसक रहा है। जनता की मुसीबतों की ओर कोई ध्यान नहीं है। इसी प्रकार से और भी दिक्कतें हैं। समस्तीपुर से दिल्ली तक एक बोगी है जिसमें अटेंडेन्ट नहीं रहता है। सुविधाओं के सम्बन्ध में इस मंत्रालय की तरफ से हमेशा लापरवाही बरती जाती है। एक अटेंडेन्ट के न रहने से दूसरे लोग उसमें घुस आते हैं लेकिन उसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसी प्रकार से समस्तीपुर से दिल्ली के लिए एक और गाड़ी चलाने की बहुत जरूरत है। इसके अलावा समस्तीपुर या दरभंगा से जयनगर के लिए एक गाड़ी की बहुत मांग है। शायद इस पर सरकार विचार भी कर चुकी है और एलान भी होने जा रहा है। वहां की जनता इस बात को जानना चाहती है कि यह गाड़ी कब तक चलाई जायेगी ?

श्री अटल बिहारी वाजपेयी (बलरामपुर) : नयी गाड़ी चलेगी तो बिना टिकट चलने वाले और बढ़ेंगे।

श्री शिव चन्द्र झा : जब सरकार सजा देती है तो उसको जनता की सुविधाओं की ओर भी पूरा ध्यान देना चाहिए। इस मंत्रालय की ओर से ऐसा सर्कुलर जारी किया जाना चाहिए कि जिन सुविधाओं की इस समय व्यवस्था है उनको मुस्तैदी से बरता जाये। कर्मचारियों की ओर से भेदभाव बरता जाता है। कोई भी उनसे पूछने जाता है तो उसको टालने की कोशिश की जाती है। रिजर्वेशन के लिए जब हम वायर करते हैं तो उसमें भी टालमटोल की जाती है। इस बीमारी का खात्मा होना चाहिए। अगर इस बीमारी का खात्मा हो जायेगा तो मैं समझता हूं जनता को बहुत लाभ पहुंचेगा। सरकार पहले ये सारी सुविधायें दे उसके बाद अगर जनता से कोई गल्तियां होती हैं तो सरकार को भी थोड़ा-बहुत हक हो जाता है कि वह सजा दे और जुर्माना करे। लेकिन मेरा निवेदन है कि सरकार ने जो जुर्माने की रकम एक्सेस चार्जेज 50 पैसे और 15 पैसे की जगह पर दस रुपये और पांच रुपये रखे हैं वह महंगाई के जमाने में बहुत ज्यादा है। इसीलिये मेरा संशोधन है कि जहां पर 10 रु० हैं वहां पर दो रु० रखे जायें और जहां पर पांच रु० का जुर्माना लगेगा वहां पर एक रु० रखा जाये। तब कुछ हद तक यह बात तर्कसंगत हो सकती है।

लोग टिकट ले कर चलें इसके लिये एक दूसरा कदम सरकार की ओर से बढ़ाने की जरूरत है, और वह है पब्लिसिटी जो स्टेशन पर होनी चाहिये। आप को मालूम होगा कि चीनी हमले के वक्त में एक छोटे से स्टेशन की मैं कहानी बताता हूँ कि जो लोग बिना टिकट चलते थे, चीनी हमले के वक्त एक ऐसा वातावरण हो गया कि जो बिना टिकट चलते थे उनके अन्दर यह भावना जागृत हुई कि अगर हम दो, चार आने का टिकट नहीं खरीदेंगे तो एक बहुत बड़ा कुकर्म करेंगे। इसलिये स्वतः बिना टिकट चलने का काम खत्म हो गया। ऐसी फ़िजा पैदा करनी होगी सरकार की तरफ से और रेलवे मंत्रालय की ओर से। अगर ऐसा किया जायगा तो नागरिकों के मन में एक नैतिकता की भावना पैदा होगी और वे सोचेंगे कि उनका कर्तव्य हो जाता है कि हम टिकट ले कर चलें। बगैर टिकट चलना वह एक गुनाह समझें। यह आप प्रचार के जरिये और शिक्षा मंत्रालय के जरिये कर सकते हैं।

सुविधायें आप बढ़ायें तभी बिना टिकट चलने का सिलसिला खत्म होगा, उस में कमी आयेगी और हमारे समाज का स्तर ऊँचा उठेगा।

इन शब्दों के साथ मैं अपना संशोधन पेश करता हूँ।

SHRI NAMBIAR (Tiruchirapalli) : I wanted to speak yesterday but the situation was such that I could not speak and I was misunderstood. I submit that I was not reponsible for that situation. However, I am thankful to you for giving me an opportunity on this subject which is very important.

Any person found travelling without a ticket has to pay a fine of Rs. 10/- now instead of 50 paise which was in vogue. I have a little knowledge of the working of the railways and I had occasion to discuss this with the commercial staff of the railways. They said that it was always easy to collect fifty paise as penalty from passenger; an ordinary passenger would pay the penalty of eight annas in addition to the fare. If Rs. 10/- is to be paid, he is unable to pay that amount and the ticket examiner has to let him off. According to the statistics given by the hon. Minister now, there is a fall in ticketless travel. These are not correct statistics because after the introduction of the new rate many ticket examiners are not in a position to collect anything and so they let off passengers with the result that the number has fallen whereas ticketless travel as such has not gone down. Those who travel deliberately without tickets...

SHRI PILOO MODY (Godhra) : ...are crooks.

SHRI NAMBIAR : They could not be caught because they know the method of travelling without tickets. Mr. Mody has a pass now; otherwise we do not know whether he will travel with or without a ticket. Persons who deliberately travel without tickets cannot be detected. Sometimes passengers are unable to get tickets because of the long queue and the last minute rush and only such persons are caught. They have not got Rs. 10/- and what happens is that they are handed over to the nearest railway station master who is supposed to collect money. Since he is unable to collect money, he has to let them off. Instead of getting more money, the railways are actually losing money. This is another example of 'penny-wise pound-foolish system'. Therefore, in the larger interests of Railway finance we submit that this is a wrong step. I do not know who has advised the Railway Minister to bring in this legislation. I think some wrong advise has been given to him. Now it is difficult for us to disprove his statement because the number will fall and he will say this is a success. But the money collected is the criterion.

There is another difficulty. Many trains are running without ticket examiners, or without being manned. Now they are thinking of introducing the new system of squad checking of trains. The trains will go without travelling ticket examiners, suddenly half-a-dozen ticket examiners will show themselves in a way-side station, they will attack the train and they will have a thorough checking. Thereby those who are

[Shri Nambiar]

caught that day may have to pay. But many who know these things will not be caught. Therefore, it is not in the larger interest of the Railway Administration to have this penalty of Rs. 10/-.

Sir, let not the hon. Minister think we are pleading for ticketless travellers. We are not doing that. But we are only saying that it is not possible for you to collect ten rupees. It will also not be possible for you to check ticketless travel by this. It is a social evil. It is an economic issue. Let us see how it can be eradicated by other means. Therefore, I would again request him to drop this measure. In the interest of Railway finance something better should be done. As the hon. Member has suggested, instead of eight annas you may raise it to Rs. 2 or Rs. 2.50. You will not get ten rupees.

There are cases where in certain parts people travel without tickets because of so many reasons but when the ticket examiner catches them they give a hundred-rupee note with the result that after deducting one rupee (eight annas plus eight annas) he is not able to give the balance of Rs. 99. These cases were reported to the Railway Administration by somebody and that is why they have advised instead of one rupee. ten rupees may be collected. This advice has been given by some person who does not know the exact situation and that is why this wrong move has been made. Therefore, in the larger interest of the Railway Administration I again plead that he may withdraw this measure. By doing so he will be doing a service to the Railway Administration and the travelling public.

THE MINISTER OF RAILWAYS (DR. RAM SUBHAG SINGH) : Sir, there is no question of raising our revenue by this penalty amount. This measure is proposed to be taken with a view to cultivating the habit of travelling with proper ticket on the railways. Therefore, though, of course, I appreciate the sentiments of hon. Members who have dwelt upon this matter, I am sorry I am not in a position to accept their advice.

MR. CHAIRMAN : The question is :

Page 2,—*for* lines 5 to 7, *substitute*—

'3. In section 113 of the Principal Act, in sub-section (3),—

Amendment of section 113

(a) in the opening paragraph, for the words "fifty naye paise", the words "ten rupees" shall be substituted ;

(b) in the first proviso, for the words "nearest multiple of five naye paise, or fifteen naye paise", the words "nearest multiple of five paise, or five rupees" shall be substituted.' (3)

The motion was adopted.

MR. CHAIRMAN : I shall put all the other amendments together.

Amendments Nos. 9 & 11 were put and negatived.

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That clause 3, as amended, stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 3, as amended, was added to the Bill.

New Clause 4

MR. CHAIRMAN : Then we come to Clause 4 (New).

Amendment made :

Page 2, after line 7, add—

Repeal and Saving 3 of 1969

'4. (1) The Indian Railways (Amendment) Ordinance 1969, is hereby repealed.

(2) Notwithstanding such repeal, anything done or any action taken under the principal Act as amended by the said Ordinance shall be deemed to have been done or taken under the principal Act as amended by this Act as if this Act had come into force on the 10th day of June, 1969.' (4)

(Dr. Ram Subhag Singh)

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That clause 4 (New) stand part of the Bill".

The motion was adopted.

Clause 4 (New) was added to the Bill.

Clause 1 (SHORT TITLE)

Amendment made :

"Page 1, lines 3 and 4,—

for "the Indian Railways (Second Amendment) Act, 1968" *substitute* "the Indian Railways (Amendment) Act, 1969" (2) (*Dr. Ram Subhag Singh*)

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That clause 1, as amended, stand part of the Bill.

The motion was adopted.

Clause 1, as amended, was added to the Bill.

Enacting Formula

Amendment made :

"Page 1, line 1,—

for "Nineteenth" *substitute* "Twentieth". (1) (Dr. Ram Subhag Singh)

MR. CHAIRMAN : The question is :

"That the Enacting Formula, as amended stand part of the Bill".

The motion was adopted.

The Enacting Formula, as amended, was added to the Bill.

The Title was added to the Bill.

DR. RAM SUBHAG SINGH : I move : "That the Bill, as amended, be passed."

MR. CHAIRMAN : The question is ...

श्री ओंकार लाल बेरवा (कोटा) : कोरम नहीं है । कैसे पास कर रहे हो ?

MR. CHAIRMAN : There is quorum.

SHRI NAMBIAR : I want to speak on the third reading.

MR. CHAIRMAN : We have already taken five hours for the Bill. Should we take more ?

SHRI NAMBIAR : I will be very brief. The hon. Minister is bent upon getting the legislation passed. When it is implemented there will be trouble between the passenger and the ticket examiner. When the passengers find that it is impossible for them to pay the penalty of Rs. 10 there will be altercation between them and the ticket examiners and there will be chaos.

SHRI PILOO MODY : So, you must make Shri Nambiar the ticket collector.

SHRI NAMBIAR : Even if you make Shri Piloo Mody, such a big person whom nobody can attack, the ticket examiner he cannot save his skin. So, you must give protection to the ticket examiner ; otherwise, he will be beaten black and blue. In fact, the ticket examiners have told me to convey their feelings to the House.

So, I would say in the end that the ticket examiners should be protected and *bona fide* passengers who could not purchase ticket for want of time should be dealt with in a humanitarian manner.

SHRI PILOO MODY : I have one suggestion to make. Let the ticket collectors be females. Then there would not be any trouble.

DR. RAM SUBHAG SINGH : All these points were discussed earlier. It is not something new. There has been trouble in the past also. We will see that all possible care is taken to protect railway employees.

MR. CHAIRMAN : The question is : "That the Bill, as amended, be passed."

The Lok Sabha divided :

Division No. 3] **AYES** [14.51 hrs.

Ahirwar, Shri Nathu Ram
Arumugam, Shri R. S.
Bajpai, Shri Vidya Dhar
Barua, Shri Bedabrata
Barua, Shri R.
Basumatari, Shri

Besra, Shri S. C.
Bhandare, Shri R. D.
Bhattacharyya, Shri C. K.
Bohra, Shri Onkarlal
Chanda, Shrimati Jyotsna
Chandrika Prasad, Shri
Chaturvedi, Shri R. L.
Choudhury, Shri J. K.
Das, Shri N. T.
Dasappa, Shri Tulsidas
Dass, Shri C.
Deshmukh, Shri B. D.
Dhillon, Shri G. S.
Dhuleshwar Meena, Shri
Dwivedi, Shri Nageshwar
Ghosh, Shri P. K.
Govind Das, Dr.
Gudadinni, Shri B. K.
Gupta, Shri Lakhan Lal
Heerji Bhai, Shri
Hem Raj, Shri
Jadhav, Shri Tulshidas
Kahandole, Shri Z. M.
Kasture, Shri A. S.
Katham, Shri B. N.
Kavade, Shri B. R.
Kinder Lal, Shri
Krishna, Shri M. R.
Krishnan, Shri G. Y.
Krishnappa, Shri M. V.
Kushok Bakula, Shri
Lakshmikanthamma, Shrimati
Lalit Sen, Shri
Laskar, Shri N. R.
Laxmi Bai, Shrimati
Mahadeva Prasad, Dr.
Mahajan, Shri Vikram Chand
Mandal, Dr. P.
Marandi, Shri
Master, Shri Bhola Nath
Masuriya Din, Shri
Minimata Agam Dass Guru, Shrimati
Mishra, Shri Bibhuti
Murti, Shri M. S.
Oraon, Shri Kartik
Palchodhuri, Shrimati Ila
Panday, Shri K. N.
Pant, Shri K. C.
Parmar, Shri Bhaljibhai
Partap Singh, Shri
Parthasarathy, Shri
Patel, Shri Manubhai
Patel, Shri N. N.
Patil, Shri C. A.
Patil, Shri Deoroa
Patil, Shri S. D.
Radhabai, Shrimati B.
Raghu Ramaiah, Shri
Raj Deo Singh, Shri
Raju, Shri D. B.
Ram Subhag Singh, Dr.
Rana Shri M. B.
Reddi, Shri G. S.
Reddy, Shri P. Antony
Reddy, Shrimati Sudha V.
Roy, Shri Bishwanath
Roy, Shrimati Uma
Sadhu Ram, Shri
Saigal, Shri A. S.
Sanji Rupji, Shri
Sankata Prasad, Dr.
Sant Bux Singh, Shri
Sarma, Shri A. T.
Sayeed, Shri P. M.
Sen, Shri Dwaipayan
Sen, Shri P. G.
Sethi, Shri P. C.
Sethuraman, Shri N.
Shambhu Nath, Shri
Sharma, Shri Naval Kishor
Shashi Bhushan, Shri
Sheo Narain, Shri
Sheth, Shri T. M.
Shinde, Shri Annasahib
Shiv Chandika Prasad, Shri
Shukla, Shri S. N.
Shukla, Shri Vidya Charan
Siddayya, Shri
Siddheshwar Prasad, Shri
Singh, Shri D. N.
Sinha, Shri Mudrika
Sinha, Shri R. K.
Snatak, Shri Nar Deo
Solanki, Shri S. M.
Sonar, Dr. A. G.
Sursingh, Shri
Tiwary, Shri K. N.
Talu Ram, Shri
Veerappa, Shri Ramachandra
Verma, Shri Balgovind
Virbhadra Singh, Shri
Vyas, Shri Ramesh Chandra

NOES

Adichan, Shri P. C.
Amat, Shri D.
Atam Das, Shri
Banerjee, Shri, S. M.
Bansh Narain Singh, Shri
Behera, Shri Baidhar
Berwa, Shri Onkar Lal
Birua, Shri Kolai

Chandra Shekhar Singh, Shri
Chauhan, Shri Bharat Singh
Fernandes, Shri George
Goyal, Shri Shri Chand
Gupta, Shri Indrajit
Jha, Shri Bhogendra
Jha, Shri Shiva Chandra
Joshi, Shri Jagannath Rao
Joshi, Shri S. M.
Kalita, Shri Dhireswar
Khan, Shri Zulfiquar Ali
Krishna, Shri S. M.
Kundu, Shri S.
Lakkappa, Shri K.
Madhok, Shri Bal Raj
Madhukar, Shri K. M.
Majhi, Shri Mahendra
Misra, Shri Srinibas
Modak, Shri B. K.
Mody, Shri Piloo
Mohammad Ismail, Shri
Mukerjee, Shri H. N.
Nambiar, Shri
Nihal Singh, Shri
Pandey, Shri Sarjoo
Paswan, Shri Kedar
Patel, Shri J. H.
Patil, Shri N. R.
Ranga, Shri
Saboo, Shri Shri Gopal
Satya Narain Singh, Shri
Sen, Dr. Ranen
Sharda Nand, Shri
Shastri, Shri Ramavtar
Shastri, Shri Sheopujan
Shivappa, Shri N.
Singh, Shri J. B.
Somani, Shri N. K.
Suraj Bhan, Shri
Thakur, Shri Gunanand
Tyagi, Shri O. P.
Viswanatham, Shri Tenneti
Yadav, Shri Ram Sewak

MR. CHAIRMAN : The result* of the devision is : Ayes : 108, Noes : 51.

The motion was adopted.

SOME HON. MEMBERS : Shame, Shame.

14.50 hrs.

UNLAWFUL ACTIVITIES (PREVENTION) AMENDMENT BILL

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF HOME AFFAIRS (SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA) : Sir, I beg to move† :

> "That the Bill to amend the Unlawfnl Activities (Prevention) Act, 1967, be taken into consideration."

It is a simple piece of legislation. Parliament has already enacted the Unlawful Activities (Prevention) Act, 1967. As the House knows, the Act was intended to deal with such people and associations which preach for cession or secession of the territory of India. At the time this legislation was brought before the House, our legal advice was that there will not be constitutional difficulty in extending the provisions of the Bill to the State of Jammu and Kashmir. As every hon. Member can see, by its very nature, the Act should extend to all parts of the country. But subsequently, when this Bill was examined with a viewpoint of legal applicability to the State of Jammu and Kashmir, we were told that, as a measure of abundant caution, we should specifically make it applicable to the State of Jammu and Kashmir. Therefore, a Presidential Order under article 170 was issued conferring the legislative power on this honourable House to pass a legislation to extend the provisions of this Bill to the State of Jammu and Kashmir also.

Sir, to make things completely clear, beyond any doubt, we have brought forward this amending Bill to make the Unlawful Activities (Prevention) Act applicable to the State of Jammu and Kashmir. This is a simple purpose of this amending Bill. I have no doubt that the House will whole-heartedly support this Bill.

AN HON. MEMBER : Why ?

SHRI VIDYA CHARAN SHUKLA : I will give you the reason why I am optimistic.

---

* The following Members also recorded their votes for 'NOES' :—
Sarvashri Jharkhande Rai, M. Meghachandra, and M. H. Gowda.

† Moved with the recommendation of the President.